श्री एस.एस. आहलुवालिया : सर, यह गलतबयानी हो रही हैं। अभी कोलकाता कारपोरेशन की रिपोर्ट आई हैं। कोलकत्ता कारपोरेशन के बारे में बंगाल विधान सभा के उनके ऐजुकेशन मिनिस्टर ने खुद कहा है कि 245 गवर्नमेंट ओन्ड स्कूलों में से सिर्फ 125 स्कूलों में ही संडास की व्यवस्था की जा सकी हैं, दूसरों में नहीं की जा सकी हैं। आप कह रहे हैं कि पूरे देश में कर दिया हैं लेकिन मैं कलकत्ता की बात कर रहा हूं। ..(व्यवधान)... आप कहिए कि प्रावधान किया हैं।

डा. रघवंश प्रसाद सिंह : हमने कहां कहा हैं कि सभी विद्यालयों में प्रबंन्ध कर दिया गया हैं? ...(व्यवधान)... हमने यह कहा हैं कि टोटल सैनिटेशन कैम्पेन में सभी विद्यालयों में पानी और पारखाने का प्रबंध करने के लिए योजना बना दी गई हैं। उसका कार्यान्वयन किया जा रहा हैं और उसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई हैं।3744 करोड़ रूपए का उसमें प्रोजेक्ट बनाया गया हैं और महोदय, यह टोटल सैनिटेशन कैम्पेन 398 जिलों में था,जिसको बढ़ाकर नए 142 जिलों में और किया गया हैं और देश भर में करीब 66 जिलों में टोटल सैनिटेशन कैम्पेन के तहत सभी के लिए प्रबंध किया जा रहा हैं और मैं समझता हूं कि सन् 2005 तक सभी विद्यालयों में पानी-पाखाने का इंतजाम कर दिया जाएगा।

Expenditure incurred on the Security of VIP's

*322. SHRI TARIQ ANWAR: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government are considering to reduce the security provided to the hundreds of VIPs;

(b) if so, the details thereof;

(c) the total number of VIPs who have been provided with the security; and

(d) the total expenditure incurred on the security of VIPs annually?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI SRIPRAKASH JAISWAL): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

श्री तारिक अनवर : सभापति महोदय, यह सही हैं कि आज हमारे देश में आतंकवाद और उग्रवाद एक जटिल समस्या है और उसको ध्यान में रखकर अगर सुरक्षा प्रदान की जाती हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, परंतु आज हमारे देश में जो सरकारी सुरक्षा दी जा रही हैं और ली

जा रही हैं, वह एक तरह से स्टेटस सिम्बल बन गया हैं। सबसे विडंबना की बात यह हैं कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले हर व्यक्ति को आज सुरक्षा चाहिए। यहां तक कि पंचायत स्तर के भी जो हमारे प्रतिनिधि हैं, वे भी आज सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा हैं कि व्यक्तियों द्वारा धारित पद और खतरे के आधार पर सुरक्षा प्रदान की जाती हैं। हम उनसे यह जानना चाहेंगे कि इतनी बड़ी संख्या में आज जो सुरक्षाकर्मी महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ उनकी सेवा में जुडे हैं उसके कारण देश और राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में कितनी अड़चन पैदा हो रही हैं?

सभापति महोदय, सभी लोग जानते हैं, खास तौर पर राजधानी दिल्ली में, कि किस तरह से ट्रैफिक के अंदर सुरक्षा को लेकर आम आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ता हें। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो लोग आज सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं, उसका रिव्यू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और किस प्रकार से, किस आधार पर उनको सुरक्षा अभी भी दी जा रही हैं?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : सर, यह एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया हैं। समय-समय पर जिन लोगों को सिक्योरिटी प्रदान की गई हैं, समय-समय पर हमारे अधिकारी उसको बैठकर रिव्यू करते रहते हैं और इसके लिए बाकायदा एक कमेटी बनी हुई हैं जिसमें स्पेशल या ऐडीशनल सेक्रेटरी चेयरमैन होता हैं, स्पेशल डायरेक्टर आई.बी. का होता हैं उस कमेटी में, स्पेशल कमिशनर दिल्ली पुलिस का होता हैं, ज्वाइटं सेक्रेटरी एम.एच.ए. का होता हैं। ये लोग बैठकर समय-समय पर रिव्यू करते रहते हैं और जहां कहीं भी आवश्यकता होती हैं, सिक्योरिटी को घटाया जाता हैं, सिक्योरिटी को बढ़ाया जाता है या सिक्टोरिटी को समाप्त कर दिया जाता हैं। यह बात सहीं हैं कि बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, ट्रैफिक की दिक्कतें होती हैं, लेकिन हमारे देश की परिस्थितियों को देखते हुए ये सारी दिक्कतें हमको भी उठानी पड़ती हैं, देश की जनता को भी उठानी पड़ती हैं।?

श्री तारिक अनवर : सर, हमारा दूसरा सवाल यह हैं कि क्या यह बात सही नहीं हैं कि बहुत से जो संदिग्ध लोग हैं, जिन पर क्रिमिनल केसेज चल रहे है, जिन पर मुकदमें चल रहे हैं, और जो बहुत ही अपराध में लिप्त रहे हैं, वैसे लोगों को सरकार सुरक्षा दे रही हैं? ऐसे कितने लोगों की सूची हैं?

श्री बलबीर के पुंज: सर ऐसे लोगों को वीआईपी की सुरक्षा ....(व्यवधान)..

श्री श्रीप्रकाश जावयवाल :सर, यह आरोप सही नहीं हैं। ...(व्यवधान)... ये आरोप सही नहीं हैं।

सभापति महोदय, आप बैठिए, बैठिए। यूं मत करिए, आप। ....(व्यवधान)... बैठ जाइए। मंत्री जी को बोलने दीजिए।....(व्यवधान)...

श्री दत्ता मेघे : सर.... (व्यवधान)...

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : यह आरोप सत्य नहीं हैं कि ऐसे लोगों को कोई सुरक्षा प्रदान की जाती हैं जो मफिया हैं और जो गलत कार्मो में लिप्त हैं। ....(**व्यवधान**)... ऐसे लोगों को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती हैं।...(**व्यवधान**) बल्कि सुरक्षा के लिए एक कमेटी होती हैं, वह सुरक्षा प्रदान करती हैं। ऐसा नहीं हैं कि माफिया या गलत लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाती हैं। मैं इस आरोप से बिल्कुल सहमत नहीं हूं।

SHRI FALI S. NARIMAN: Sir, I only rise to say one thing to the Ministry. After 56 years of our independence, must we not get rid of the concept VIP"? Who is a VIP in this country Surely, there are Presidents, Vice-Presidents, Judges, etc. They are all important people; they perform their duties. And, I would respectfully submit that when we profess equality, when we talk from the housetops about equalities and inequalities and go to the courts for it, why should we have this special category of citizens viz V.I.P.s. or V.V.I.P.s? It is an obnoxious category, and I object to it. If they are terrorist-infected persons, then, call them. TIPs, if you like. But let us not have this category of VIPs. There is no very important person. Everyone is as important or as unimportant as the other. Abolish the word, Minister.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : सर हमारे देश के हालत से पूरा देश वाकिफ हैं। जिस तरीके की आंतकवाद की घटनाएं हुई हैं, जिस तरीके से देश को आतंकवादियों ने निशाने पर बनाने की कोशिश की हैं। इसलिए यह संभव नहीं हैं कि किसी को कोई सुरक्षा न दी जाए या आतंकवादियों से अगर उनका भय हैं तो उनको सुरक्षा प्रदान न की जाए और जो देश के लिए कार्य कर रहे हैं, उस कार्य से उनको रोका जाए। इसलिए ऐसा संभव नहीं हैं लेकिन इसको समय-समय पर हमारी रिव्यू कमेटी रिव्यू करती हैं। जिसको आवश्यकता होती हैं, उसी को सिक्योरिटी कम कर दी जाती हैं या सुरक्षा बढ़ा दी जाती हैं।

श्रीमती सविता शारदा : सर आसाम में आतंकवादियों ने इतने लोगों को मार दिया इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। जो वी.आई.पी. नहीं हैं. आम आदमी हैं उनके लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था हैं?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल :सर, यह वी.आई.पी.सिक्योरिटी से संबंधित प्रश्न हैं इसलिए इसका कैसे उत्तर दिया जाए।

श्रीमती सविता शारदा :सर, वी.आई.पी. के साथ-साथ उन्होंने कहा हैं कि आम जनता के लिए क्या व्यवस्था हैं?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल :इस प्रश्न से उसका कोई संबंध नहीं हैं।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : सभापति महोदय, वी.आई.पी. की सिक्योरिटी व्यवस्था पर जो जवाब आया हैं, उसे पढकर लगता हैं कि ऐसा ही जवाब हैं कि क्या कार्यवाही की जाती हैं, क्या नहीं की जाती हैं। उनकी सुरक्षा हो, इसलिए उनकी जान की रक्षा करने के लिए सुरक्षा दी जाती हैं। बेअंतसिंह के पास सुरक्षा थी, बुलटेप्रूफ गाड़ी थी,लेकिन उनको बचा नहीं सके।

इंदिरा जी के पास सुरक्षा थी, लेकिन उनको बचा नहीं सके। इसी तरह बहुत सारे वी.आई.पीज. को पूरी सुरक्षा दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं बचा सके। किन्तु आज सिर्फ वी.आई.पी. को सुरक्षा देने के नाम पर, आज जो आसाम में घटना घटी हैं, उसमें स्कूली बच्चों को अगर सुरक्षा व्यवस्था हुई होती तो यह घटना नहीं घटती। वहां इंडिपेंडेंस डे का एक वी.आई.पी. प्रोग्राम था, टेरोरिस्ट इनफेक्टिड एरिया का प्रोग्राम था, चूंकि वहां कोई वी.आई.पी. नहीं आ रहा था इसलिए कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी इसलिए आई.ई.डी. लगा दिया गया। सिर्फ जहां पर वी.आई.पी. की मूवमेंट होगी, वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। क्या आम जनता की सुरक्षा के लिए कोई कारगुजारी की जा रही हैं?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : सर देश की आम सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में अगर कोई प्रश्न होता तो उसका हम जवाब दे सकते थे।...(**व्यवधान**)... यहां पर तो वी.आई.पी. की सुरक्षा का प्रश्न हैं उसका जवाब हमने दे दिया हैं। जहां कहीं भी ...(**व्यवधान**)... देंगे। ....(**व्यवधान**)...

श्री एस.एस. आहलुवालिया : ये मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने सीधे सवाल किया हैं कि इंदिरा जी को सुरक्षा प्राप्त थी, उसके बाद उनकी हत्या हुई। सुरक्षा थी, बुलटेप्रुफ गाड़ी थी और बेलटप्रुफ जैकेट वाले सिक्योरिटी एजेंट थे, उसके बावजूद बेअंतसिंह की हत्या हुई। सुरक्षा होते हुए, राजीव गांधी जी की हत्या हुई। सुरक्षा के लिए, इसकी बात छोड़िए। सुरक्षा मिलने के बावजूद आप सुरक्षा नहीं कर सकते तो आम जनता की सुरक्षा कैसे करेंगे?...(व्यवधान).... आप कैजुअल जवाब तो दीजिए।

श्री सभापति : आप यह चाहते हैं कि वी.आई.पी. की सुरक्षा के लिए जो इंतजाम किए हैं, वे नहीं होने चाहिए।

श्री एस.एस. आहलुवालिया : सभापति जी, फुलप्रूफ तो हो। ये जनता के बारे में फुलप्रूफ नहीं हैं।

श्री सभापति : यह बता दें कि फुलप्रूफ होना चाहिए।

गृह मंत्री श्री शिवराज वी. पाटिल : आपने जो कहा हैं, वपह बात हम सब लोगों के ध्यान में हैं, इसके लिए यह नहीं कहा जा सकता कि वह बात सहीं नहीं हैं। मगर मैं यह भी आपके सामने

रखना चाहूंगा कि आम जनता की सुरक्षा के लिए सारा पुलिस बल हैं,स्टेट का पुलिस बल हैं, केंद्र का पुलिस बल हैं और कभी-कभी तो हम अपने सुरक्षा बलों की मदद लेकर भी काम करते हैं। यह बात सहीं हैं कि इतना होने पर भी वी.आई.पी. की हत्या हो जाती हैं, इतना होने पर भी ऐसे कई हादसे हो जाते हैं, जिसकी वजह से जान-माल का नुकसान होता हैं। ऐसा न हों, यह करने के हम कदम उठाते आए हैं, आगे और ज्यादा कदम उठाएंगे। आप सब लोगों से राय लेंगे इसमें क्या तब्दीली की जा सकती हैं, इसे भी हम देख सकते हैं। मगर यह मानना सहीं नहीं हैं कि केवल वी.आई.पी. की सुरक्षा की बात की जाती हैं, आम आदमी की सुरक्षा की नहीं की जाती हैं। आम जनता के लिए स्टेट की पुलिस, गवर्नमेंट आफ इंडिया की पुलिस हैं तथा सुरक्षा बल भी काम करते हैं।

MR. CHAIRMAN : Next question.

SHRIMATIVANGAGEETHA: Question No. 323 ..... *(Interruptions)*

प्रो. रामदेव भंडारी : सभापति जी, मुझे 322 पर सवाल पूछना हैं।

श्री सभापतिः नहीं, वह हो गया हैं।

प्रो. रामदेव भंडारी : सभापति जी, मेरा सवाल हैं। ...(व्यवधान)..

श्री सभापति : यह गलत बात हैं....(व्यवधान)... वे बोल रही हैं

प्रो. रामदेव भंडारी : सभापति जी,

श्री सभापति : क्वेश्चन दूसरा आ गया हैं ....(**व्यवधान**)...

प्रो. रामदेव भंडारीः सभापति जी, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि ....(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः नहीं आप बैठ जाइए....(**व्यवधान**)...

प्रो. रामदेव भंडारी : सभापति जी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं ....(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : मैं अलाऊ नहीं कर सकता हूं ....(**व्यवधान**)... माननीय सदस्य आप बैठ जाइए....(**व्यवधान**)...

प्रो. रामदेव भंडारी : सभापति जी, जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं और पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा की तो व्यवस्था हो रहीं है, मगर जो पूर्व उप प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए उसी तरह से ट्रैफिक रोका जाता हैं....(**व्यवधान**)....

श्री सभापति : चलिए बैठ जाइए ....(**व्यवधान**)...

प्रो. रामदेव भंडारी : इनके लिए भी उसी प्रकार से ट्रैफिक रोका जाताद हैं, इससे बड़ी कठिनाई होती हैं। इस पर भारी व्यय होता हैं....(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : बैठिए, बैठिए ...(**व्यवधान**)...

प्रो. रामदेव भंडारी : इनके लिए भी ऐसी व्यवस्था करने की क्या आवश्यकता हैं। सभापति जी, पूर्व प्रधानमंत्री ठीक हैं लेकिन पूर्व उप प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसी व्यवस्था करने की क्या आवश्यकता हैं ...(**व्यवधान**)... इसकी क्या आवश्यकता हैं. ...(**व्यवधान**)....

श्री सभापति : बैठ जाइए, हो गया ...(**व्यवधान**)... काफी हो गया हैं ...(**व्यवधान**).. बैठ जाइए ....(**व्यवधान**)...

प्रो. रामदेव भंडारी : हम लोगों को ट्रैफिक के कारण दिक्कत होती हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : बैठ जाइए ...(**व्यवधान**)...

प्रो. रामदेव भंडारी : इनके लिए इसकी क्या आवश्यकता हैं ....(**व्यवधान**).... सभापति जी, इनकी वजह से भारी ट्रैफिक जाम हो जाता हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैने आपको अलाऊ नहीं किया हैं...(**व्यवधान**)... दूसरा क्वेश्चन बोल दिया गया हैं ...(**व्यवधान**)... आप बैठ जाइए...(**व्यवधान**)...

प्रो. रामदेव भंडारी : सभापति जी, क्या आवश्यकता हैं....(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : आप बैठ जाइए, माननीय सदस्य ...(**व्यवधान**)... नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमती वंगा गीता ....(**व्यवधान**)... आप बैठ जाइए ....(**व्यवधान**)... आपकी बात खत्म हो गई ...(**व्यवधान**)... बैठ जाइए ...(**व्यवधान**)... आपका टाइम खत्म हो गया। श्रीमती वंगा गीता

Non-utilisation of funds under the Rural Drinking Water Schemes

*323. SHRIMATI VANGA GEETHA: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the outlay for the Rural Drinking Water Schemes is not being utilized fully for years together;

(b) the reasons for non-utilisation of funds by the States for drinking water in rural areas; and